उन का ध्यान इस तरफ़ खींचते हैं लेकिन उन के पास दूसरे ऐसे काम हैं जिन को वह ज्यादा महत्व का समझते हैं और डैंटल क्लीनिक्स उनको जितनी खोलनी चाहिएं वह नहीं खोल रहे हैं । हम फिर उन का ध्यान इधर खींच रहे हैं । अब इस से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री को डर है कि अगर ऐसी ही हालत बनी रही और स्टेट्स जवाब नहीं देंगी तो २० साल में हम सब लोग दांतों के बग़ैर हो जायेंगे तो वह जानना चाह रहे हैं कि सैंटर उस के लिए क्या विशेष कार्यवाही कर रहा है ?

Shri A. P. Jain: I thought the hon. Minister said that some sort of dental assistance could be given to MPs. My artificial teeth are getting loose. Can I get free artificial teeth replacement?

Mr. Speaker: That question should not be put so directly. Can a Member of Parliament get his denture replaced?

Shri Tyagi: Personal questions are objectionable in Parliament. Nobody can further his own cause here.

Mr. Speaker: Therefore, I did not allow that question, but modified it by asking whether a Member of Parliament can get his dentures replaced.

Dr. Sushila Nayar: No, supply of dentures is not included in the dental services.

Mr. Speaker: Shri Jaipal Singh.

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि डैंटल डिके का सब से बड़ा कारण . . . .

Mr. Speaker: I called Shri Jaipal Singh.

Shri Jaipal Singh: Is the hon. Minister in a position to enlighten us whether vegetarians have a harder time in dental hygiene than non-vegetarians and whether prohibitionists are more vulnerable to dental decay than anti-prohibitionists?

Dr. Sushila Nayar: The hon. Member is completely wrong. Prohibition has no relation to the health of the teeth and vegetarians are no more vulnerable to tooth decay than non-vegetarians.

Shri A. P. Jain: That is very encouraging to the hon. Member!

श्री कछवाय: क्या यह बात सही है कि दांतों में खराबी आने और उन में रोग पैदा होने का एक सब से बड़ा कारण दांतों के नये नये मंजन हैं जोकि बाज़ार में बिकते हैं ?

डा० सुशीला नायर : किसी मंजन का दोष तो हमें मालूम नहीं है लेकिन खाने के तुरन्त बाद कुल्ला करने की आदत लोगों में कम हो रही है जिस से कि दांतों को ज़रूर नुकसान हो रहा है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि भारत संसार में अकेला ऐसा अभागा देश है जहां कि डालडा और कोटोजम की सब से ज्यादा खपत है और यही डालडा और कोटोजम डैंटल डिके का सब से बड़ा कारण है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, डालडा, काटोजम के कई दोष हो सकते हैं लेकिन दांतों के डिके का उस के साथ सम्बन्ध है यह मैं ने आज नई बात सुनी है ।

गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रैस, नासिक

*६७४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रैस, नासिक में कुछ अन्य देशों के नोट तथा डाक टिकट छपने इस बीच बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सिक्योरिटी प्रैस में दूसरे देशों के नोट छापने का काम बन्द कर दिया गया है लेकिन

दूसरे देशों के डाक-टिकट अब भी वहां छापे जाते हैं ।

(ख) दूसरे देशों ने खुद ही नासिक प्रैस को नोट छापने के आर्डर देने बन्द कर दिये । इस मामले में उनसे लिखा-पढ़ी इसलिए नहीं की गयी कि एक तो इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस में पहले से ही काम का बहुत ज़ोर है और दूसरे विदेशी मुद्रा (फ़ारेन-एक्सचेंज) की तंगी के कारण उन देशों के आर्डर पूरे करने के लिए नोट छापने के काम आने वाला कागज़ बाहर से मंगाने के लिए हम विदेशी मुद्रा की कोई भी रक़म खर्च नहीं कर सकते ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि नासिक के सिक्योरिटी प्रैस में दूसरे किन-किन देशों के नोट छपते थे और क्या उन्होंने इसलिए हमारे यहां आर्डर देना बन्द कर दिया कि उन की छपाई समय पर नहीं होती थी या अच्छी छपाई नहीं होती थी ? आखिर किस कारण उन के नोट छपने बन्द हो गये ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी बात नहीं है । उदाहरण के लिए हम नेपाल के नोट छापते थे, जिन का छपना अब बन्द हो गया है । उन के लिए जो पोस्टेज स्टैम्प और दूसरे कागज़ छापे जाते हैं, उन में बाहरी कागज़ लगता है । इस लिए हम ने नेपाल सरकार से कहा कि अगर वह बाहरी कागज़ मंगा कर हम को दे, तो हम इन को छापें, क्योंकि हम बाहरी कागज़ मंगाने के लिए अपना फ़ारेन एक्सचेंज नहीं ख़र्च कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि हाउस के सब तरफ़ बातें हो रही हैं, जिन की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । —मेरे कहने के बावजूद भी कई जगह बोलना बन्द नहीं हुआ है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि नासिक के सिक्योरिटी प्रैस में, जहां एक एक कागज़ के ऊपर बड़ी सावधानी और निगरानी रखी जाती है वहां की क्या ऐसी घटना भी कोई वित्त मंत्री के कानों में पड़ी है कि प्रैस के सब से बड़े अध्यक्ष ने उस प्रैस में क्रिसमिस के कार्ड छपवाये । अगर आज वह क्रिसमिस के कार्ड छपवा सकते हैं, तो कल नोट भी छपवा सकते हैं । इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने क्रिसमिस कार्ड छपवाने के बारे में जो सूचना दी है, मैं उस की छानबीन करूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी पूछा जाता है, मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, हम जानकारी लेंगे, आदि । माननीय मंत्री को सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए । आप इस विषय में उन को आदेश दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । बाकी बहुत से माननीय सदस्यों का जवाब तो वह दे देते हैं, मगर चूंकि स्वामी जी की बात बहुत गहरी होती है, इसलिए शायद वह जवाब न दे सकें । उस के लिए उन को तैयार रहना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री विश्राम प्रसाद : सिक्योरिटी प्रैस, नासिक में जो कागज़ नोट छापने के लिए बाहर से आता है, उस के लिए भारत सरकार को कितना रुपया ख़र्च करना पड़ता है और क्या उस तरह का कागज़ अपने देश में ही बनाने की व्यवस्था हो रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सवाल दूसरे देशों के लिए नोट आदि छापने के बारे में है । हम अपने यहां के लिए नोट आदि छापने के लिए कितना कागज़ मंगाते हैं, यह एक अलग सवाल है । अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे, तो मैं उस का जवाब दूंगा । जहां तक बाहरी देशों के लिए नोट, पोस्टेज

स्टैम्प या स्टेशनरी छापने का सवाल है, हमारा जो ख़र्चा लगता है, वह हम ले लेते हैं। जहां तक बाहर का कागज़ मंगाने का सवाल है, वे मंगा कर दें, तो हम छापें ।

Shri Kapur Singh: May I know if the Nasik Security Press is now omni-competent to meet all our requirements of security printing? If not, to what other countries do we take resort to have our requirements?

Shri B. R. Bhagat: For our security printing we do not go to any other country. We have been expanding it to meet all our requirements.

श्री सरजू पाण्डेय : मंत्री जी ने अभी बताया कि बाहरी देशों के नोट और डाक-टिकट छापे जाते थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि बर्मा के अतिरिक्त और किन-किन देशों के नोट और डाक-टिकट छापे जाते थे ।

श्री ब० रा० भगत : बर्मा के पोस्टेज स्टैम्प छपते हैं और नेपाल के करेंसी नोट छपते हैं । सिक्किम और भूटान के भी छपते हैं ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य देशों के नोट छापना कब से बन्द हुआ और इस समय कितने छपते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : नोट तो अब नहीं छपते हैं । पोस्टेज स्टैम्प थोड़े छपते हैं लेकिन उन के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री कछवाय: नोटों को छापना कब से बन्द हुआ ?

U.S. Loans

+

*675. **Shri P. C. Borooah:**
Shri D. C. Sharma:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether three agreements providing for U. S. Loans totalling $39.6 million (Rs. 18.6 crores) for three projects had been signed in October this year; and

(b) if so, which are the projects to be financed therewith?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): (a) and (b). The following three project agreements totalling $39·55 million were signed in October, 1963.

(i) Central Ropeway-"F" Project Establishment of a plant and aerial ropeway to extract and transport sand and use it for stowing in the Jharia Coal Field, Bihar— $7.7 million;

(ii) Chandrapura Thermal Electric Power Project Stage II—Establishment by DVC of a 140 MW thermal electric power unit with auxiliary facilities at Chandrapura Station, Bihar—$16·0 million.

(iii) Purchase by Indian Railways of 54 Broad Gauge Diesel eletric locomotives including necessary spare parts and training of personnel —$15.85 million.

Shri P. C. Borooah: What are the terms of the agreements and to what level US Loans to India have been reached after the conclusion of these agreements?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: These agreements were signed in October 1963. These loans are repayable in dollars over a period of forty years with a grace period of ten years. The hon. Member knows that the US Agency for International Development charges no interest but only a credit fee of ¾ to 1 per cent per annum.

Shri P. C. Borooah: The second part of the question how far total loan had been received—has not been answered.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: The agreement has been signed only in